vinetur

जर्मनी में शराब पर 20% कर वृद्धि से खपत मुश्किल से घटेगी, AOK का कहना

ड्राफ्ट से स्पिरिट्स पर केवल कुछ सेंट का इजाफा होगा, जबकि बीयर और वाइन, जो अधिकांश खपत का आधार हैं, इससे अप्रभावित रहेंगे।

गुरुवार, 24 सितंबर 2026



AOK Federal Association के अनुसार, स्वास्थ्य-सम्बंधी उत्पाद शुल्कों के जर्मनी में प्रस्तावित उपयोग का अलग-अलग उत्पादों पर बहुत भिन्न असर पड़ सकता है। संगठन ने कहा कि शराब पर प्रस्तावित कर वृद्धि नशे की खपत को रोकने में शायद बहुत कम असर डालेगी, क्योंकि यह बहुत छोटी है और बीयर व वाइन को इससे छूट मिलेगी।

बुधवार को प्रकाशित एक ऑडियो साक्षात्कार में, AOK Federal Association में रोकथाम प्रमुख ओलिवर हुइजिंगा ने कहा कि तथाकथित steering taxes तब प्रभावी जन-स्वास्थ्य उपकरण हो सकती हैं, जब उन्हें इस तरह तैयार किया जाए कि वे कीमतों या उत्पाद-फॉर्मूलेशन में सार्थक बदलाव लाएँ। उन्होंने तंबाकू, शराब और मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स पर संघीय सरकार की मौजूदा योजनाओं को इस शुरुआती परीक्षा के रूप में देखा कि क्या जर्मनी उस रास्ते से आगे बढ़ने को तैयार है, जिसे AOK ने कमजोर रोकथाम रिकॉर्ड कहा है।

ये टिप्पणियाँ Public Health Index 2025 के प्रकाशन के बाद आई हैं, जो AOK ने German Cancer Research Center के साथ मिलकर तैयार की एक रिपोर्ट है। AOK ने कहा कि दिसंबर 2025 में जारी इस सूचकांक में समीक्षा किए गए 18 यूरोपीय देशों में जर्मनी 17वें स्थान पर रहा। समूह के अनुसार, तंबाकू, शराब और पोषण नीति में जर्मनी लगभग सबसे नीचे रहा, जबकि शारीरिक गतिविधि के मामले में उसका प्रदर्शन कुछ बेहतर था।

हुइजिंगा ने कहा कि इस सूचकांक ने यह दिखाने में मदद की कि जर्मनी अब भी सीमित रोकथाम उपायों पर कितना निर्भर है, खासकर उस माहौल को आकार देने के मामले में जिसमें लोग स्वास्थ्य-संबंधी फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि तब से संघीय सरकार ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले उत्पादों को लक्षित करते हुए कई कर उपायों की घोषणा की है या उन पर काम शुरू किया है।

उन्होंने ऐसे करों को तंबाकू और शराब जैसे उत्पादों की खपत घटाने का एक “बहुत प्रभावी” तरीका बताया, खासकर युवाओं सहित संवेदनशील समूहों में। उन्होंने यह भी कहा कि ये कर राजस्व भी पैदा कर सकते हैं, जिसका उपयोग या तो स्वास्थ्य व्यवस्था को समर्थन देने के लिए किया जा सकता है या, बेहतर होगा, रोकथाम प्रयासों के वित्तपोषण के लिए।

लेकिन हुइजिंगा ने सरकार के तंबाकू प्रस्ताव और शराब प्रस्ताव के बीच स्पष्ट अंतर किया। तंबाकू के मामले में, उन्होंने कहा, मौजूदा मसौदा “काफी अच्छा” है क्योंकि यह कई वर्षों में पर्याप्त मूल्य वृद्धि पैदा करेगा। अगर इसे प्रस्तावित रूप में लागू किया गया, तो उनके अनुसार इसका सार्थक निवारक असर हो सकता है और संसद में इसे और मजबूत भी किया जा सकता है। उन्होंने जोड़ा कि एक मजबूत तंबाकू कर समय के साथ हजारों नए कैंसर मामलों को रोक सकता है।

शराब करों पर उनका आकलन अधिक संशयपूर्ण था। सरकार के मसौदे के तहत, स्पिरिट्स, स्पार्कलिंग वाइन और अल्कोपॉप्स पर कर 20% बढ़ेंगे। हुइजिंगा ने कहा कि सुनने में यह बड़ा लगता है, लेकिन व्यवहार में यह एक व्यक्तिगत पेय पर केवल छोटी-सी बढ़ोतरी में बदलेगा, यानी लगभग कुछ सेंट, या एक लॉन्ग ड्रिंक पर करीब पाँच सेंट। उनके विचार में, उपभोक्ताओं को यह बदलाव मुश्किल से महसूस होगा और इसलिए इसका निवारक प्रभाव भी बहुत कम होगा।

उन्होंने बीयर और वाइन को छूट देने के फैसले की भी आलोचना की, और कहा कि जर्मनी में शराब खपत का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा इन्हीं का है। क्योंकि ये श्रेणियाँ बढ़ोतरी के दायरे से बाहर रहेंगी, हुइजिंगा ने कहा कि मौजूदा मसौदे से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई महत्वपूर्ण असर पड़ने की संभावना नहीं है।

यह अंतर पेय क्षेत्र के लिए मायने रख सकता है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि प्रस्ताव से तत्काल मूल्य दबाव मुख्य रूप से स्पिरिट्स, स्पार्कलिंग वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक अल्कोहल मिक्स पर पड़ेगा, जबकि बीयर और वाइन उत्पादक फिलहाल इस उपाय से बाहर रहेंगे। यदि मसौदा बिना बदलाव के रहता है, तो उपभोक्ता मांग पर संभावित असर मादक पेयों के बीच असमान हो सकता है, और कुल शराब खपत पर दबाव भी सीमित रह सकता है।

हुइजिंगा ने एक अलग कर पर भी चर्चा की, जिसे सरकार 2027 से शक्कर-युक्त पेयों पर लागू करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आगे की विधायी प्रक्रिया के लिए कानूनी आधार जुलाई 2025 में पारित उस कानून में शामिल था, जिसका उद्देश्य वैधानिक स्वास्थ्य बीमा योगदान दरों को स्थिर करना था। शराब और तंबाकू करों के विपरीत, उन्होंने कहा, मीठे पेयों के लिए लक्ष्य मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को महँगा बनाना नहीं है। इसके बजाय, उद्देश्य निर्माताओं को शर्करा की मात्रा कम करने के लिए प्रेरित करना होगा।

उन्होंने ब्रिटेन के मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स पर लागू tiered levy को एक मॉडल के रूप में इंगित किया। AOK के अनुसार, उस दृष्टिकोण से सॉफ्ट ड्रिंक्स में शर्करा स्तर में पर्याप्त कमी आई, क्योंकि इसने निर्माताओं को उत्पादों का पुनः-निर्माण करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन दिया। हुइजिंगा ने कहा कि अब तक के संकेत बताते हैं कि जर्मन सरकार Health Finance Commission की सिफारिश का पालन कर सकती है और इसी तरह की संरचना अपना सकती है।

ऐसे में मुख्य असर खुदरा कीमतों के बजाय रेसिपी और उत्पाद संरचना पर पड़ने की संभावना होगी। पेय निर्माताओं के

लिए इसका मतलब अल्पकालिक मांग प्रभावों के बजाय संभावित reformulation लागत और पोर्टफोलियो बदलावों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, खासकर उच्च शर्करा वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स में।

यह बहस इस बात से भी जुड़ी है कि जर्मनी अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का वित्तपोषण कैसे करने की योजना बना रहा है। हुइजिंगा ने कहा कि Health Finance Commission ने सिफारिश की थी कि इन steering taxes से होने वाला राजस्व वैधानिक स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था की मदद करे और स्थिर योगदान दरों का समर्थन करे। लेकिन फिलहाल, उन्होंने कहा, तंबाकू और शराब करों से होने वाला अतिरिक्त राजस्व सीधे वैधानिक स्वास्थ्य बीमा में जाने के बजाय सामान्य संघीय बजट में ही जाएगा।

उन्होंने कहा कि चीनी कर से होने वाले राजस्व के साथ कम-से-कम राजनीतिक स्तर पर अलग व्यवहार किया जा रहा है। हुइजिंगा के अनुसार, सरकार ने वादा किया है कि शक्कर-युक्त पेयों पर लेवी से मिलने वाला राजस्व स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था के लिए संघीय सब्सिडी में होने वाली कटौती की भरपाई में मदद करेगा। क्या यही सिद्धांत आगे चलकर तंबाकू और शराब करों पर भी लागू होगा, यह अभी खुला है और संसद में बहस का हिस्सा बन सकता है।

उन्होंने कहा कि Bundestag की स्वास्थ्य समिति के सांसदों ने व्यापक रूप से तर्क दिया है कि इन धनराशियों का उपयोग न केवल बीमा व्यवस्था के समर्थन में होना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य संवर्धन से भी अधिक स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना चाहिए। इसमें कार्यस्थलों, डे-केयर केंद्रों, स्कूलों और नगरपालिकाओं में रोकथाम पर खर्च शामिल हो सकता है।

Health Finance Commission की दूसरी रिपोर्ट दिसंबर 2026 में अपेक्षित है और वह जर्मनी की वैधानिक स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था को स्थिर करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक उपायों पर केंद्रित होगी। हुइजिंगा ने कहा कि उस चर्चा में रोकथाम को केंद्रीय भूमिका निभानी होगी, क्योंकि उनके अनुसार, देश के बुजुर्ग होने के साथ आबादी के समग्र स्वास्थ्य में सुधार किए बिना व्यवस्था को समय के साथ स्थिर रखना मुश्किल होगा।

उन्होंने कहा कि AOK उम्मीद करता है कि आयोग केवल करों से आगे बढ़कर साक्ष्य-आधारित प्रस्ताव पेश करेगा। विशेष रूप से, उन्होंने विज्ञापन और विपणन प्रतिबंधों को ऐसे क्षेत्र के रूप में इंगित किया जहाँ जर्मनी में अब भी बड़ी खामियाँ हैं। उन्होंने कहा कि शराब का विज्ञापन रोजमर्रा की जिंदगी में अब भी व्यापक है, बिक्री स्थल पर तंबाकू प्रचार की अभी भी अनुमति है, और उच्च शक्कर, वसा और नमक वाले खाद्य उत्पादों का अभी भी कार्टून पात्रों और खिलौना उपहारों के साथ विपणन किया जा सकता है।

हुइजिंगा ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कानूनी रोकथाम-आदेश को मजबूत किया जा सकता है और नगरपालिकाओं पर रोकथाम तथा स्वास्थ्य संवर्धन प्रदान करने की अधिक औपचारिक बाध्यता हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संवर्धन अक्सर इसलिए विफल हो जाता है क्योंकि शहरों और कस्बों के पास अपने वित्तीय संसाधन नहीं होते, और यदि जर्मनी सार्वजनिक-स्वास्थ्य उपायों का व्यापक क्रियान्वयन चाहता है, तो इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।